



WRITERS CREW INTERNATIONAL RESEARCH

JOURNAL

आर्थिक समृद्धि बनाम ग्रामीण वित्तीय समावेशन
(जौनपुर जनपद के संदर्भ में)

कमल पाण्डेय

शोधार्थी

समाजशास्त्र विभाग,

मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश



सारांश

वित्तीय समावेशन" और "समावेशी विकास" आज प्रचलित शब्द हैं। समावेशी विकास कमजोर वर्गों के लोगों को सशक्त बनाता है। यह, बदले में, कई कारकों पर निर्भर करता है - सबसे महत्वपूर्ण है "वित्तीय समावेशन", जो समावेशी विकास को बढ़ावा देने में रणनीतिक भूमिका निभाता है और कमजोर वर्गों को वित्त के नियमित और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करके गरीबी को कम करने में मदद करता है। इस दिशा में, भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के अपने अभियान में बैंक रहित परिवारों तक औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और उनका लाभ उठाने के लिए कई उपाय किए हैं। इस पेपर का उद्देश्य वित्तीय समावेशन की प्रकृति और सीमा और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कमजोर वर्गों से संबंधित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर इसके प्रभाव का आकलन करना है। इसका विश्लेषण वित्तीय पहुंच और आर्थिक विकास पर सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एकत्र प्राथमिक आंकड़ों का विश्लेषण करके किया गया है। नतीजे बताते हैं कि वित्तीय समावेशन की प्रकृति और सीमा में असमानता है।

औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच और उनका लाभ उठाने से कमजोर वर्गों के परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त होता है, जो सहसंबद्ध होते हैं, जिससे समावेशी विकास होता है, जिसके आधार पर पेपर वित्तीय प्रणाली को और अधिक समावेशी बनाने के लिए एक मॉडल का प्रस्ताव करता है।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 महत्वपूर्ण आर्थिक रुझानों को उजागर करने वाली एक उल्लेखनीय रिपोर्ट है। ग्रामीण भारत में संपत्ति के स्वामित्व, रोजगार, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष (एमवाईएस) और सामाजिक समावेशन के मामले में। स्थानिक आकस्मिक श्रम, गरीबी, किसान कार्ड के माध्यम से कम पहुंच, वित्तीय के चिंताजनक निष्कर्षों को देखते हुए पिरामिड के निचले भाग के



लोगों के लिए समावेशन गंभीर नीतिगत चुनौतियाँ पैदा करता है। अखबार का तर्क है कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण जो अवसर, सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, सही होगा आगे बढ़ने का रास्ता। नीति प्रभावशीलता सूचकांक (पीईआई) दृष्टिकोण हमारे असंतोषजनक कानून के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और व्यवस्था की स्थिति और खराब रोजगार के अवसर। यह ग्रामीण शहरी प्रवासन से बचने की वकालत करता है रणनीति; इसके बजाय यह कृषि (आर एंड डी), कृषि उद्योग विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि में निवेश का आह्वान करता है विकास और मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) को एकजुट करने के लिए कौशल प्रशिक्षण।

यह पेपर इसकी पहचान से निपटने का प्रयास करता है। सेवा केंद्र और स्थानिक व्यवस्था की गणना जौनपुर जिले में सेवा केन्द्रों का पूरक क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला। अध्ययन क्षेत्र स्थित है मध्य गंगा मैदान का पूर्वी उत्तर प्रदेश। अध्ययन है विशेष रूप से ब्लॉक स्तर पर एकत्र किए गए द्वितीयक डेटा पर आधारित विभिन्न कार्यालयों सा केंद्रीयता स्कोर की गणना की गई है कार्यात्मक केंद्रीयता जैसे तीन प्रकार के सूचकांकों के आधार पर सूचकांक, कार्यशील जनसंख्या सूचकांक और तृतीयक जनसंख्या सूचकांक।

पाँच में से न्यायिक रूप से चुने गए 31 कार्य या सेवाएँ हैं क्षेत्र (प्रशासनिक, कृषि और वित्तीय, शैक्षिक, स्वास्थ्य और परिवहन और संचार) को मापने के लिए सेवा केंद्र की केंद्रीयता. थीसेन बहुभुज और बेरी मापने के लिए ब्रेकिंग पॉइंट विधि का उपयोग किया गया है पूरक क्षेत्र। कुल 88 सेवा केन्द्र बनाये गये हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें क्रम की सेवा के रूप में पहचान की गई केंद्र।

कीवर्ड: वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन का प्रभाव, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, समावेशी विकास



1. परिचय

आर्थिक साहित्य में 'समावेशी विकास' को संसाधनों के न्यायसंगत आवंटन के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलता है। यह अर्थव्यवस्था के विकास में समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों की भागीदारी और विकास का लाभ प्राप्त करना है, जो विकास में समानता के उद्देश्य को प्राप्त करता है। समावेशी विकास की अवधारणा को 'सभी के लिए समान अवसरों के साथ आर्थिक विकास' कहा जाता है। यह विकास के अवसर पैदा करने और उन्हें सभी के लिए, विशेषकर गरीबों के लिए सुलभ बनाने के अलावा और कुछ नहीं है (अली और जुआंग, 2007)।

वित्तीय समावेशन वंचित और निम्न-आय समूहों के विशाल वर्गों को किराया लागत पर वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी है। रंगराजन समिति, भारत सरकार (2008), वित्तीय समावेशन को 'कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों जैसे कमजोर समूहों के लिए किराया लागत पर वित्तीय सेवाओं और समय पर, जहां आवश्यक हो, पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया' के रूप में परिभाषित करती है। . यह 'हाशिये पर पड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने' का एक प्रयास है जो आबादी के सभी वर्गों और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को शामिल करते हुए समावेशी विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, गरीबी उन्मूलन के लिए वित्त तक पहुंच एक पूर्व शर्त है जो विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कमजोर वर्गों के परिवारों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच से वंचित रखा गया है। इसे लोकप्रिय रूप से वित्तीय बहिष्करण के रूप में जाना जाता है, जो दुर्गमता, दूरियों, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और गरीब परिवारों की कम अवशोषण क्षमता के कारण होता है जो विकास में बाधा डालता है। अखिल भारतीय स्तर पर और कर्नाटक में वित्त तक पहुंच के संकेतकों पर डेटा एक समान परिदृश्य की पुष्टि करता है।

इस समस्या का आगे अध्ययन करना और एक प्रभावी गरीब समर्थक वित्तीय समावेशन नीति बनाना जो गरीबी में कमी, संसाधनों और क्षमताओं के समान वितरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य को प्राप्त



करे, समय की मांग है। औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके समावेशी विकास को बढ़ावा देने की यह चुनौती इस पेपर की पृष्ठभूमि है। भारत में, राष्ट्रीय योजनाओं की शुरुआत से ही समान विकास को बढ़ावा देने में वित्त की भूमिका पर जोर दिया गया है। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं ग्रामीण सहकारी समितियों की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सामाजिक बैंकिंग, ग्रामीण ऋण पर सरकारी नीतियों में दिया गया ध्यान।, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, लीड बैंक योजनाएं, ब्याज दर सीमा, सब्सिडी, आदि। भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में इस नीतिगत दबाव के बाद भी, औपचारिक बैंकिंग सेवाएं परिवारों के विशाल क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाई हैं और समाज के गरीब और सीमांत वर्गों तक नहीं पहुंच पाई हैं। किसी भी वित्तीय सेवा तक पहुंच हो।

"गरीबी अपमान है, उन पर निर्भर होने की भावना है और अशिष्टता, अपमान और स्वीकार करने के लिए मजबूर होना है।" जब हम मदद मांगते हैं तो उदासीनता होती है", एक लातवियाई महिला का कहना है। की पहली सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना पढ़ना स्वतंत्र भारत में लगभग 60% (504 मिलियन) ग्रामीण गरीबों की असहायता को कोई भी महसूस नहीं कर सकता।

2000 में लातविया की गरीब महिला के कथन की मार्मिकता। भारत की 66% आबादी ग्रामीण भारत में है केवल 13.7% (2014) जीडीपी हिस्सेदारी वाली जनसंख्या। यह प्रच्छन्न रोजगार (नर्कसे) द्वारा चिह्नित है, द्वारा विभाजित जाति की राजनीति (कोठारी)। इसलिए, वर्तमान सर्वेक्षण सामयिक और ज्ञानवर्धक है क्योंकि यह ताज़ा जानकारी सामने लाता है। ग्रामीण भारत के निचले स्तर पर परिप्रेक्ष्य। रिपोर्ट चतुराई से ओबीसी के जातिगत डेटा को इकट्ठा करने से बचती है; संभवतः जाट आरक्षण मामले (राम सिंह बनाम यूओआई: 2015) में सुप्रीम कोर्ट की तीखी आलोचना के कारण। एक अर्थ यह है कि यह जनगणना ग्रामीण भारत के सामाजिक आयाम के बजाय आर्थिक आयामों पर अधिक केंद्रित है। यह लेख (ए) विभिन्न प्रकार के अभावों के संदर्भ में अखिल भारतीय प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है



(बी) परिसंपत्ति स्वामित्व, रोजगार, साक्षरता और सामाजिक समावेशन की अंतरराज्यीय प्रोफाइल (सी) के लिए नीति विकल्प ग्रामीण भारत को विकास की कहानी में मुख्यधारा में लाना और (डी) आगे का रास्ता।

किसी भी क्षेत्र में विकासात्मक वृद्धि हर जगह और अकेले ही शुरू नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है विभिन्न तीव्रताओं के साथ बिंदुओं या विकास ध्रुवों का रूप, फिर यह विभिन्न के साथ विस्तारित होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर अलग-अलग अंतिम प्रभाव वाले चैनल (पेरोक्स, 1955)। कोई भी स्थायी बस्तियाँ जिनके पास आस-पास की सामाजिक और आर्थिक माँगों को पूरा करने के लिए कुछ कार्य होते हैं। क्षेत्रों को सेवा केंद्र के रूप में जाना जा सकता है। जनसंख्या, मौजूदा बुनियादी सुविधाएं, सेवा केंद्र की पहचान करने के लिए दूरी और लोगों की आवाजाही का उपयोग किया गया है पूरक क्षेत्र. सेवा केन्द्र के संबंध में अनेक विद्वानों द्वारा अध्ययन किया गया हैगरस्ट्रैंड (1952), बेरी (1967) और सेन एट अल। (1971). कुछ विद्वानों ने प्रयास भी किया है

विभिन्न क्षेत्रों में क्रिस्टेलर (1933) और लॉस्च (1954) के सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए अनुभवजन्य अध्ययन। उनमें से महत्वपूर्ण हैं स्माइल्स (1944), पेरोक्स (1950), ब्रश (1953), ब्रेसी (1953), मिश्रा और शिवलिंगैह (1970), मिश्रा (1972, 1974), रॉय और पाटिल (1977) आदि। मिश्रा, आर.पी. (1974) केंद्रीय स्थान सिद्धांत के मूल तत्वों को एकीकृत करके 'ग्रोथ फ़ॉर्सी' की अवधारणा को प्रतिपादित किया, विकास ध्रुव सिद्धांत और नवाचार सिद्धांत का स्थानिक प्रसार और प्रस्तावित पांच-स्तरीय पदानुक्रम ग्रोथ पोल (राष्ट्रीय स्तर), ग्रोथ सेंटर (क्षेत्रीय स्तर), ग्रोथ प्वाइंट के रूप में ऊपर से नीचे तक (उप-क्षेत्रीय स्तर), सेवा केंद्र (सूक्ष्म क्षेत्रीय स्तर), केंद्रीय गांव के रूप में विकास केंद्र (स्थानीय स्तर)। इसके अलावा, कुछ उल्लेखनीय विद्वान जिन्होंने भू-स्थानिक उपकरण और तकनीकों को लागू किया था क्षेत्रीय योजना बनाने वाले थे मिश्रा (1985), आर.के. मल्लिक (1998), एल.आर. यादव और आर.एस. सिंह (2009), सरकार (2018), खान और अहमद (2013), चतुर्वेदी (2013), आदि।



2.1 पृष्ठभूमि/उद्देश्य:

चूंकि किसी राष्ट्र/क्षेत्र/राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास की अवधारणाएं मानव संसाधनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस पेपर का उद्देश्य सुधार के बाद की अवधि में उत्तर प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास की जांच करना है।

तरीके/सांख्यिकीय विश्लेषण:

उत्तर प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा की गणना करके परीक्षण किया गया है

दशकीय वृद्धि दर, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, और उचित समय श्रृंखला भूखंडों का निर्माण करके।

विशेष रूप से, राज्य की आर्थिक रूपरेखा वास्तविक सकल राज्य घरेलू की सहायता से प्रस्तुत की गई है कारक लागत पर उत्पाद। और, सरकार की मदद से विकास के सामाजिक पहलू की जांच की गई है

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय।

2.2 जाँच - परिणाम:

अध्ययन के निष्कर्षों से मानव विकास के निम्न स्तर और परिणामी निम्न स्तर का पता चलता है

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विकास। यह विशिष्ट रूप से देखा गया है कि सभी आर्थिक का औसत प्रदर्शन 2012 और 2015 के दौरान राज्य में सामाजिक क्षेत्रों में भी गिरावट आई है। यह अवलोकन उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है राज्य में बेरोजगारी, गरीबी और असमानता का कायम रहना।

2.3 सुधार/अनुप्रयोग:

सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए उचित नीतिगत पहल की आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश का आर्थिक पिछड़ापन खास तौर पर जनता के विकास पर ध्यान देना जरूरी है



पिरामिड के तल पर।

2.4 आर्थिक वृद्धि और विकास

राष्ट्रीय विस्तार के सन्दर्भ में आर्थिक वृद्धि एवं विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण है

धन और लोगों का उच्च जीवन स्तर [1]। इस प्रकार, विकास प्रयासों का लक्ष्य सदैव वृद्धि करना होता है रोजगार के अवसर प्रदान करके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके लोगों की भलाई और जीवन की गुणवत्ता असमानता को कम करना. माइकल टोडारो के शब्दों में, "आर्थिक विकास जीवन स्तर में वृद्धि है, आत्म-सम्मान की जरूरतों में सुधार और उत्पीड़न से मुक्ति के साथ-साथ बढ़िया विकल्प"[2]।

जब हम देखते हैं हमारी मातृभूमि भारत में हम देखते हैं कि इसकी आय ऊपरी आय की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही है अर्थव्यवस्थाएँ। इसके अलावा, हम सामाजिक-आर्थिक प्रगति में धीमी गति देखते हैं जो इसके राज्यों/क्षेत्रों में असमान है।

मानव कल्याण के महत्वपूर्ण उपाय - जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, और साक्षरता दर - भिन्नताएँ दर्शाते हैं पूरे भारतीय राज्यों में यह कम और उच्च प्रदर्शन के बीच अंतरराष्ट्रीय विरोधाभासों के मामलों के समान है अर्थव्यवस्थाएँ [3]। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का मामला उल्लेखनीय है। हालांकि उत्तर प्रदेश इस मामले में तीसरे नंबर पर है

महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद अर्थव्यवस्था का आकार, लेकिन यह इतना विकसित नहीं है, और इसे इनमें से एक माना जाता है भारत के सबसे गरीब राज्य. जनसंख्या की दृष्टि से यह दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश के बराबर है [4]। ऊपर में 1,12,00 गाँवों और कस्बों में 160 मिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं। समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, उत्पादक

यूपी में कृषि आधार, विविध औद्योगिक क्षमता और बहुत बड़े बाजार का अस्तित्व इसका इंजन हो सकता है इसकी अर्थव्यवस्था का विकास, और देश के अन्य हिस्सों को समर्थन देने की भी क्षमता है [5]।



2010-11 में वृद्धि यूपी में जीडीपी की दर 8.08 फीसदी रही. इतनी विकास उपलब्धियों के बावजूद, राज्य को बड़े पैमाने पर खतरा है

गरीबी, आर्थिक और गैर-आर्थिक दोनों आयामों में। राज्य को आपूर्ति में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

सामाजिक सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। राज्य न केवल भारत के लिए एक गंभीर विकास चुनौती है, बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी, क्योंकि जब तक गरीबी काफी हद तक कम नहीं हो जाती, आर्थिक लाभ क्षमता को खाया नहीं जा सकता।

2.5 वित्तीय समावेशन के आयाम

वित्तीय समावेशन की आपूर्ति और मांग पक्ष की खोज से पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन की अवधारणा के संबंध में एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है। भारत में, वर्तमान में, वित्तीय समावेशन सभी को बचत बैंक खाते तक न्यूनतम पहुंच प्रदान करने तक ही सीमित है। यह देश की आम जनता या नागरिकों को बैंकिंग की न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना है। इसके साथ ही वित्त तक पहुंच की दो चरम संभावनाएं हैं। पहला, उन ग्राहकों के समूह के साथ जिन्हें सभी औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिलती है और दूसरे उस समूह के साथ जो वित्तीय रूप से बहिष्कृत है और सबसे बुनियादी वित्तीय उत्पादों तक पहुंच से वंचित है। इन दो संभावनाओं के बीच, बैंकों के ऐसे ग्राहक भी हैं जो वित्त तक पहुंच के लचीलेपन के बिना केवल जमा और निकासी के लिए बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं। कई संभावनाओं का यह परिदृश्य इंगित करता है कि वित्तीय समावेशन एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें विशिष्ट क्षेत्र के एजेंडे के लिए प्रासंगिक कई आयाम हैं।

3. सामाजिक-आर्थिक विकास

सामाजिक-आर्थिक विकास कोई पूर्व निर्धारित स्थिति नहीं है बल्कि यह सुधार की एक सतत प्रक्रिया है



जीवन स्तर का स्तर. इसका तात्पर्य अधिकतम लोगों तक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता से है कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन की वृद्धि और प्रगति के संबंध में पर्याप्त मात्रा में और अन्य बुनियादी सुविधाएं [6]। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास की जांच करने के लिए, द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है।

ये डेटा हैंडबुक सहित विभिन्न प्रकाशित स्रोतों से एकत्र किए गए थे

भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी, भारतीय रिज़र्व बैंक, 2015-16, सीएमआईई-भारत के राज्य डेटाबेस, हैंडबुक भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी, भारतीय रिज़र्व बैंक, 2015-16, और भारत की जनगणना, भारत सरकार, 2011. सबसे पहले, उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकीय विशेषताओं की जांच करने के लिए, ग्रामीण जैसे संकेतक यूपी की जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में, शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में, और वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का उपयोग किया गया है। दूसरे चरण में चक्रवृद्धि वार्षिक गणना करते हुए राज्य की आर्थिक प्रोफाइल की जांच की गई है

तीन वर्षों के छह समूहों के लिए विकास दर (सीएजीआर) (1991-93, 1994-96, 1997-99, 2000-02, 2003-05, 2006-08, 2009-11) और चार साल का एक समूह (2012-15) और फिर इसकी तुलना अखिल भारतीय स्तर से की जाती है।

आर्थिक प्रोफाइल कारक लागत पर वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) जैसे चर को ध्यान में रखती है, कृषि, उद्योग विनिर्माण और सेवाओं के लिए कारक लागत पर वास्तविक क्षेत्रीय राज्य सकल घरेलू उत्पाद क्षेत्र। आखिरी चरण में यूपी के विकास के सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखकर



जांच की गई है समय के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय जैसे संकेतक 1991-93 से 2012-14 तक की अवधि

3.1 आर्थिक विकास में वित्त की भूमिका

आर्थिक विकास में वित्त की भूमिका पर साहित्य में, यह वकालत की गई है कि वित्तीय विकास मांग-आपूर्ति तंत्र के माध्यम से अर्थव्यवस्था में विकास-समर्थक स्थितियां बनाता है। अठारहवीं सदी में एडम स्मिथ (1776) ने यह विचार व्यक्त किया था कि स्कॉटलैंड में बैंकों के उच्च घनत्व और स्कॉटिश अर्थव्यवस्था के विकास के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। वाल्टर बैजहोट (1873) और जॉन हिक्स (1969) ने तर्क दिया कि वित्तीय समावेशन ने पूंजी जुटाने के माध्यम से इंग्लैंड के औद्योगीकरण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। शुम्पीटर (1912) का विचार था कि एक अच्छी तरह से काम करने वाला बैंकिंग नेटवर्क तकनीकी नवाचारों को जन्म देता है। वर्ष 1952 में, जोन रॉबिन्सन ने कहा कि 'आर्थिक विकास और वित्तीय सेवाओं की मांग के बीच एक पारस्परिक संबंध है और आर्थिक प्रणाली इस परिवर्तन के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है।' साइमन कुज़नेट्स (1955, 1963) और काल्डोर (1966) ने विकास के शुरुआती चरणों में विकास और सामाजिक न्याय के बीच एक व्यापार-बंद की ओर इशारा किया जब तक कि विकास का लाभ पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं फैल गया। आधुनिक विकास सिद्धांत पर विश्व बैंक के साहित्य (2005) में कहा गया है कि 'विभिन्न पीढ़ियों की वित्तीय पहुंच, विकास और आय की गतिशीलता की प्रगति बारीकी से संबंधित है।

सामाजिक वैज्ञानिकों के एक समूह (अधियन और बोल्टन, 1997; अधियन, कैरोली और गार्सिया-पेनालोसा, 1999; बनर्जी और न्यूमैन, 1993; गैलोर और ज़ेरिया 1993; राजन और ज़िंगलेस, 2003) ने तर्क दिया कि, पूंजी बाजार की अपूर्णता को देखते हुए, कमजोर वर्ग के घर जिनकी सीमांत उत्पादकता अधिक है, उनके पास अपनी शिक्षा में निवेश करने के लिए बहुत कम पैसा होगा और कम प्रारंभिक बंदोबस्ती के कारण उनके व्यावसायिक विकल्प सीमित हैं। किंग और लेविन (1993) ने बताया



कि, तकनीकी नवाचार के लिए बैंकिंग पहुंच एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है। एक अच्छी तरह से विकसित वित्तीय प्रणाली तेज और न्यायसंगत विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। 2004 में पैट्रिक होनोहन द्वारा 160 देशों में वित्त तक पहुंच को मापने के लिए एक सूचकांक से पता चला कि उच्च सूचकांक वाली अर्थव्यवस्थाएं उन्नत अर्थव्यवस्थाएं थीं और गहरी वित्तीय प्रणाली वाले समाजों में पूर्ण गरीबी का स्तर कम था। वर्ष 1998 में बांग्लादेश में पिट और खांडकर के ग्रामीण बैंक और एमएफआई अध्ययन ने घरेलू व्यय पर ऋण के उपयोग का एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव साबित किया; संपत्ति, श्रम आपूर्ति, और बच्चों के स्कूल जाने की संभावना। वर्ष 1999 में पूर्वोत्तर थाईलैंड में माइक्रोक्रेडिट उधारकर्ताओं पर कोलमैन के अध्ययन ने भौतिक संपत्ति, बचत, स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय, शिक्षा आदि पर क्रेडिट का नगण्य प्रभाव साबित किया।

4.उद्देश्य

अध्ययन में प्रयास किया गया है:

- (i) सेवा केन्द्रों की पहचान करना
- (ii) सेवा केन्द्रों की स्थानिक व्यवस्था का निरीक्षण करना
- (iii) सेवा केंद्र के पूरक क्षेत्र और स्थानिक-कार्यात्मक अंतराल का अध्ययन करना क्षेत्र।
- (iv) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के परिवारों के बीच वित्तीय समावेशन की प्रकृति और सीमा का विश्लेषण करना।
- (v) कमजोर वर्गों के परिवारों पर वित्तीय समावेशन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का आकलन करना।
- (vi) प्रभावी वित्तीय समावेशन नीति के लिए एक मॉडल का सुझाव देना जिससे परिवारों को लाभ होगा।



5.वैचारिक ढांचा

वित्तीय समावेशन का विश्लेषण करने के उद्देश्यों और कमजोर वर्गों के परिवारों पर इसके प्रभाव को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन, वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के प्रभाव और अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास को जोड़ने वाला एक वैचारिक ढांचा सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के आधार पर तय किया गया है (चित्र 1)). तदनुसार, वित्तीय समावेशन की प्रकृति का विश्लेषण औपचारिक वित्तीय संस्थानों के प्रकार और संख्या और परिवारों द्वारा प्राप्त सेवाओं को देखकर किया गया है। वित्तीय समावेशन की सीमा को विभिन्न आय और परिसंपत्ति स्तरों पर वित्तीय सेवाओं की पहुंच और औपचारिक वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के वर्षों की संख्या को देखकर निर्धारित किया गया है। औपचारिक वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के बाद घर में होने वाले भौतिक, संज्ञानात्मक, धारणात्मक और संबंधपरक परिवर्तनों की खोज करके वित्तीय समावेशन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का आकलन और मात्रा निर्धारित की गई है।

5.1भारत में वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति

भारत सरकार की 68वीं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 80 मिलियन से अधिक गरीब लोग भारत के शहरों और कस्बों में रह रहे हैं और उनके पास बचत खाते, क्रेडिट जैसी सबसे बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। , प्रेषण, और भुगतान सेवाएँ, वित्तीय सलाहकार सेवाएँ, आदि, और वे अपनी बचत और ऋण आवश्यकताओं के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं। आर्थिक रूप से बहिष्कृत वर्गों में बड़े पैमाने पर ग्रामीण जनता शामिल है जिसमें सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, मौखिक पट्टेदार, स्व-रोज़गार और असंगठित क्षेत्र के उद्यम, शहरी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, प्रवासी, जातीय अल्पसंख्यक और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूह, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं शामिल हैं।

5.2 धारणाएँ

अध्ययन की मूल धारणा यह है कि अन्य चीजें स्थिर रहने पर, वित्तीय समावेशन से परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सकारात्मक बदलाव आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के परिवारों का 'समावेशी विकास' होता है। वर्तमान अध्ययन में, 'समावेशी विकास' को औपचारिक



वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के बाद ग्रामीण और शहरी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में हुए 'विकास' या 'सकारात्मक परिवर्तन' के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे संयुक्त स्कोर पर मापा जाता है। वित्तीय समावेशन के घटक और औपचारिक वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने का प्रभाव।

5.3 अध्ययन क्षेत्र

जौनपुर जिला (25° 26' उत्तर से 26° 11' उत्तर और 82° 8' पूर्व से 83° 5' पूर्व) पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है मध्य गंगा मैदान का. अध्ययन क्षेत्र का क्षेत्रफल 4035 वर्ग किमी है और इसकी आबादी 4035 वर्ग किमी है

44,94,204 व्यक्ति (जनगणना 2011)। जिले में दस नदियाँ बहती हैं, जैसे-गोमती, सई, वरुणा, बसुही, पीली, तम्बूरा, मोंगर, गांगी, बेसू और नंद नदी। गोमती और सई जिले के मध्य भाग में नदियाँ बहती हैं (चित्र 1)। जिले की सतह लगभग समतल है जबकि कुछ नदी क्षेत्रों के भाग में तरंग-उतार-चढ़ाव देखा जाता है।

6. भूगोल

बिहार प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग का घर है। मधुबनी पेंटिंग की जड़ें पौराणिक कथाओं में हैं। ऐसा माना जाता है कि जब सीता का विवाह राम से हुआ, तो उनके पिता राजा जनक ने ग्रामीणों से उनके विवाह का जश्न मनाने के लिए अपने घरों की दीवारों को रंगने के लिए कहा। इसलिए मधुबनी को मूल रूप से दीवारों पर चित्रित किया गया था। जब भारत भीषण अकाल से जूझ रहा था, तब बिहार की महिलाओं ने इन्हें कपड़े पर चित्रित करना शुरू कर दिया और समाज में पितृसत्ता की इच्छा के विरुद्ध इसे आर्थिक कल्याण के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया।



6.1 जगह:

जौनपुर निर्देशांक 24.24N से 26.12N और 82.70E और 83.50E के बीच पाया जाता है। यह समुद्र तल से 79.5-88.4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जिला वाराणसी मंडल के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। जिले का क्षेत्रफल 4038 वर्ग किमी है। (जौनपुर का भूगोल, एन.डी.)।

6.2 स्थलाकृति और नदियाँ:

जौनपुर काफी हद तक समतल है, जिसमें कई उथली नदी घाटियाँ हैं। जौनपुर में गोमती और सई सदाबहार बहती रहती हैं। वरुणा, मामूर, गंगी और पिली इस क्षेत्र में पाई जाने वाली छोटी नदियाँ हैं। बहने वाले जल निकायों की संख्या के कारण, जौनपुर में अक्सर बाढ़ आती है, और नदी घाटियों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में दोमट, मिट्टी-प्रकार की मिट्टी होती है (भौगोलिक जानकारी, एन.डी.)।

6.3 खनिज और मिट्टी:

क्षेत्र में रेत और बजरी के खनन और उत्खनन कार्यों से अयस्क प्राप्त होता है जिसका उपयोग निर्माण उद्योग में उपयोग के लिए चूना पैदा करने के लिए किया जाता है। हालाँकि, कुल मिलाकर, जौनपुर अधिक खनिजों का उत्पादन नहीं करता है (भौगोलिक जानकारी, एन.डी.)।

6.4 तापमान:

जौनपुर जिले का तापमान न्यूनतम 4.30C और अधिकतम 44.60C के बीच रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 987 मिमी (भौगोलिक जानकारी, एन.डी.) है।

6.5 जनसांख्यिकी (जिला जनगणना पुस्तिका जौनपुर, 2011)

जनसंख्या की दृष्टि से जिला जौनपुर प्रदेश में 7वें स्थान पर है। लिंगानुपात (1,024) के मामले में जौनपुर जिला प्रथम स्थान पर है, जो राज्य के औसत प्रति हजार पुरुषों पर 912 महिलाओं से अधिक है।



जौनपुर जिला 71.5% के साथ साक्षरता में 22वें स्थान पर है जो राज्य के औसत 67.7% से अधिक है। जिले के 3,381 गांवों में से 94 गांव निर्जन हैं। y जिले में राज्य के लगभग 2% घर (सामान्य, संस्थागत और बेघर) हैं, जिसमें प्रति घर 6.8 लोगों की औसत से 663,513 घर हैं।

6.6 शिक्षा

शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जौनपुर में कुल साक्षरता दर 71.5% है। जौनपुर में पुरुष साक्षरता दर 77.3% और महिला साक्षरता दर 57.2% (जिला जनगणना पुस्तिका जौनपुर, 2011) के बीच बहुत बड़ा अंतर है। स्कूल (जिला प्रारंभिक शिक्षा रिपोर्ट कार्ड - जौनपुर, 2016): जौनपुर में 2355 गांवों में 260 क्लस्टर और 5585 स्कूल फैले हुए हैं। जौनपुर में निजी स्कूलों की संख्या 2127 है और नामांकन 447,999 छात्रों का है। सरकारी स्कूलों की संख्या 3361 है और नामांकन 387,894 छात्रों का है। मदरसों की संख्या 97 है और नामांकन संख्या 18,564 छात्र हैं। जिला प्रारंभिक शिक्षा रिपोर्ट कार्ड से निष्कर्ष - जौनपुर, 2016: 99% स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए शौचालय हैं। वर्ष में केवल 35% स्कूलों में बिजली है। लड़कियों का नामांकन 50% है।

विकलांग बच्चों के लिए स्कूल पहुंच में सुधार करने के लिए, रैंप का निर्माण किया गया है। वर्ष दर वर्ष 65% स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक 100 लड़कों पर 98 लड़कियों का नामांकन अनुपात है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (2010) के मूल्यांकन के आंकड़ों के अनुसार, बाल श्रम को खत्म करने के लिए लगभग 50 स्कूलों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 30 क्रियाशील हैं, जिनसे 2500 बच्चों में से लगभग 1400 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। 1400 बच्चों में से 603 लड़के और 797 लड़कियाँ हैं (भारत में बाल श्रम पुनर्वास, 2010)।



6.7 स्वास्थ्य

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) (2005-2012) खराब स्वास्थ्य परिणामों वाले राज्यों में ग्रामीण आबादी को प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल, पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। मिशन का विशेष ध्यान ग्रामीण, महिलाओं और बच्चों की किफायती प्राथमिक देखभाल तक पहुंच में सुधार लाने पर है। एनआरएचएम का मुख्य लक्ष्य नवजात देखभाल, टीकाकरण, प्रसवपूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल को बढ़ावा देकर शिशु, बाल और मातृ मृत्यु दर को कम करना है। उपरोक्त प्रकाश में, हमने एनआरएचएम में निर्धारित प्राथमिक लक्ष्यों की तुलना में जमीनी स्तर पर डेटा का विश्लेषण करने का प्रयास किया है।

6.8 आजीविका कृषि:

जौनपुर जिले में कृषि आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। कुल कार्यशील जनसंख्या 32% में से 68% कृषि में संलग्न हैं। जौनपुर जिला पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में स्थित है। जिले के कुल क्षेत्रफल का 70% खेती योग्य है (2.79 लाख हेक्टेयर।) जिले की कुल श्रमिक आबादी में से 38% कृषक हैं, 30% खेतिहर मजदूरों के रूप में लगे हुए हैं, 6% घरेलू उद्योग में और 25% अन्य में लगे हुए हैं। पुरुष श्रमिकों में 38% कृषक हैं जबकि महिला श्रमिकों में 37% किसान हैं। इसी प्रकार 26% पुरुष खेतिहर मजदूरों की तुलना में महिलाओं का अनुपात 37% है (जिला जनगणना पुस्तिका जौनपुर, 2011)

6.9 उद्योग:

जौनपुर में भारी उद्योगों का अभाव है और कृषि जिले में आर्थिक विकास का प्राथमिक स्रोत है। यहां दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, अर्थात् सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA500 एकड़) और सिधवान (50 एकड़) (जौनपुर जिले का संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफाइल, 2011)। स्थापित की गई कुछ प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ हैं, हॉकिन्स प्रेशर कुकर लिमिटेड, पेप्सी फूड्स, अमित ऑयल लिमिटेड,



बैद्यनाथ आयुर्वेदिक उत्पाद, साक्षी डिटर्जेंट आदि। जिले में प्रचलित अन्य व्यावसायिक विकल्प कालीन बनाना, लकड़ी और फर्नीचर, मरम्मत और सर्विसिंग हैं। वस्त्र, चमड़ा आधारित और ईट भट्ठे।

वाराणसी-जौनपुर राजमार्ग भी औद्योगिक गतिविधि के लिए एक हॉटस्पॉट है, जहां करंजा कला के पास कपास मिलें, डेयरी इकाइयां और पशुपालन चालू हैं (भौगोलिक जानकारी, एन.डी.)।

6.10

7. डेटा बेस और कार्यप्रणाली

वर्तमान अध्ययन विभिन्न सरकारी कार्यालयों से एकत्र किये गये द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है

उत्तर प्रदेश की प्राथमिक जनगणना सार (2011), जिला जनगणना पुस्तिका, कृषि रिपोर्ट

कृषि भवन से, जिला सांख्यिकी पत्रिका, विकास भवन से और विभिन्न वेबसाइटों से। आंकड़ा

केंद्रीयता फंक्शन इंडेक्स (सीएफआई) का उपयोग करके समग्र फंक्शन इंडेक्स के लिए सारणीबद्ध और विश्लेषण किया गया, कार्यशील जनसंख्या सूचकांक (WI) और तृतीयक जनसंख्या सूचकांक (TI)।

केन्द्रीयता सूचकांक के साथ गणना की गई भारोत्तोलन तकनीक की सहायता. यहां बेरी "ब्रेकिंग प्वाइंट इक्वेशन" और थीसेन का भी उपयोग किया गया सेवा केंद्र के सेवा क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए बहुभुज विधियाँ। माइक्रो सॉफ्ट एक्सेल और आर्क जीआईएस 10.2 सॉफ्टवेयर का उपयोग क्षेत्रीय विविधता में गणना और कार्टोग्राफिक प्रस्तुति के लिए किया गया है विकास का।

7.1 सेवा केंद्र की पहचान

वर्तमान अध्ययन में सेवा के क्रम की पहचान के लिए जिले के सभी 3287 गांवों को इंगित किया गया है

केन्द्र; इसलिए संभावित सेवा केंद्रों का चयन करने के लिए नमूनाकरण तकनीकों का उपयोग किया गया है। मैं



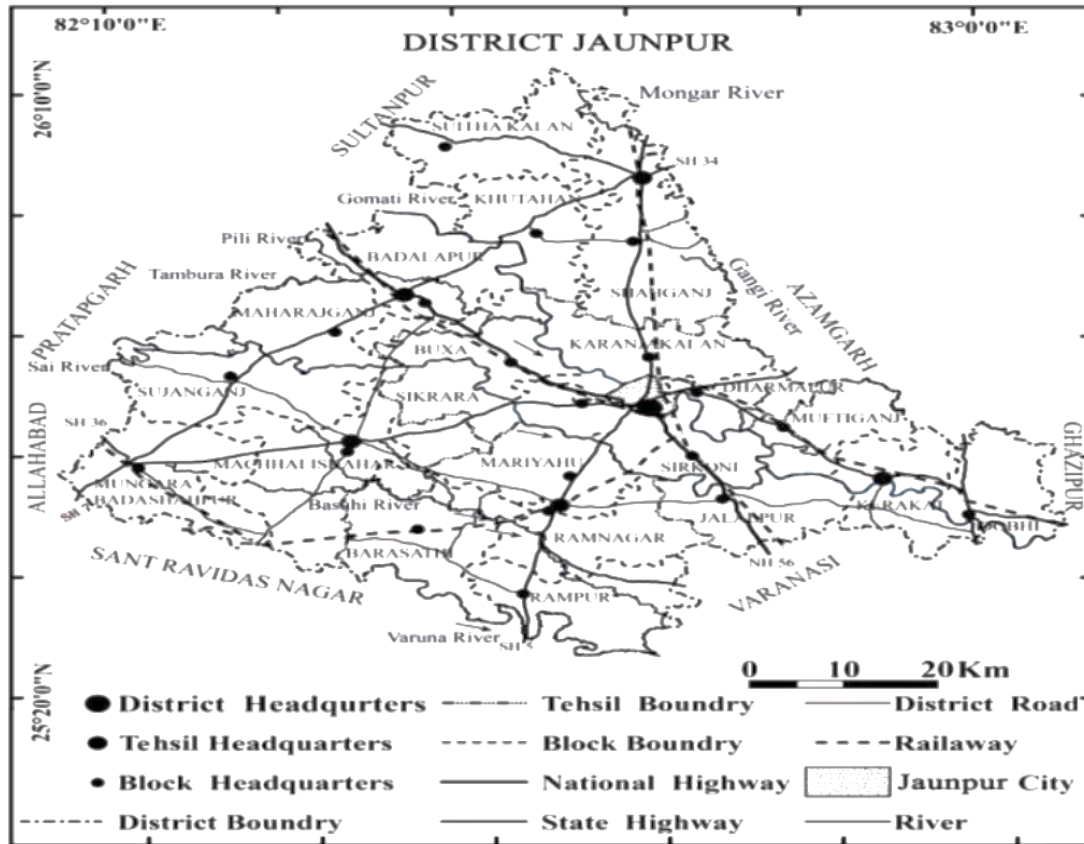
इस प्रकार, पदानुक्रम को मापने के लिए 88 संभावित गांवों (केंद्रों) का चयन किया जाता है

नीचे दिए गए मानदंडों पर विचार करके केंद्रों का स्तर:

- (i) एक स्थिर बस्ती जिसकी जनसंख्या न्यूनतम 2000 हो;
- (ii) इसमें सभी कार्यात्मक समूहों से कम से कम पांच बुनियादी कार्य होने चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और परिवहन, आदि;
- (iii) सेवा केंद्र रेल या सड़क परिवहन से जुड़ा होना चाहिए;
- (iv) इसका कुल जनसंख्या में कम से कम 0.10 प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए; और
- (v) इसमें कार्यात्मक केंद्रीयता सूचकांक के रूप में कम से कम 0.13 मान होने चाहिए।

कुछ मामलों में, जनसंख्या की आवश्यक संख्या से संबंधित पहले मानदंड को नजरअंदाज कर दिया जाता है

जहां कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से उच्च कार्यात्मक उपलब्धता है (तालिका नंबर एक)



8. परिणाम और चर्चा

8.1 केन्द्रीयता का मापन

अनेक भारतीय विद्वानों ने सेवा केन्द्र की केन्द्रीयता की गणना भी इसी आधार पर की है खुदरा क्षेत्रों या

वाणिज्यिक गतिविधियों या तृतीयक सेवाओं में लगी जनसंख्या (सिंह, 1966; सिंह 1971; सिंह,

1977)। भट्ट (1976) ने केन्द्रीयता की गणना के लिए एक भार तकनीक का उपयोग किया था।

सेवा केन्द्रों की. कुछ विद्वानों ने बस्तियों के कार्यात्मक पदानुक्रम को आधार बनाकर मापा है

लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रों की पसंद पर (सेन एट अल., 1971; कायस्थ और मिश्रा,

1981; मिश्रा, 1985)। इस अध्ययन में, कंपोजिट का उपयोग करके सेवा केंद्रों का पदानुक्रम निकाला



गया है कार्यात्मकता सूचकांक (सीएफआई) तीन सूचकांकों पर आधारित है (i) कार्यात्मक केंद्रीयता सूचकांक, (ii) कार्य करना जनसंख्या सूचकांक, और (iii) तृतीयक जनसंख्या सूचकांक।

8.2 कार्यात्मक केन्द्रीयता सूचकांक मूल्य (एफसीआई)

एफसीआई किसी भी केंद्र की कार्यात्मक उपलब्धता का माप है। इसे जोड़कर गणना की गई है

किसी भी केंद्र के सभी उपलब्ध कार्यों का वेटेज और फिर इसे संयुक्त रूप से विभाजित किया जाता है

सभी चयनित केंद्रों का वेटेज। इस अध्ययन में कृषि और वित्त (चित्र 2 ए), शैक्षिक

(चित्र 2 बी), स्वास्थ्य (चित्र 2 सी), परिवहन और संचार (चित्र 2 डी) और परिवहन प्रकार 31

एफसीआई की गणना के लिए कार्यों या सेवाओं को लिया गया है।

इसकी गणना इस प्रकार की जा सकती है:

$$\text{एफसीआई} = \text{FCI} = \sum_i^n \frac{Wid}{W} \times 100$$

जहां, FCI, एफसीआई = कार्यात्मक केंद्रीयता सूचकांक

Wid, चौड़ाई = डीटीएच केंद्र के लिए वेटेज

W=सभी केंद्रों का कुल वेटेज

8.2.1 कार्यशील जनसंख्या सूचकांक (डब्ल्यूआई)

WI की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करने के बाद की गई है:

$$WId = \frac{\bar{W}d}{Wt} \times 100$$

जहां WId = डीटीएच केंद्र का कार्यकर्ता सूचकांक



डब्ल्यूडी = डीटीएच केंद्रों की कार्यशील जनसंख्या

Wt= जिले में कुल कार्यशील जनसंख्या

8.2.2 तृतीयक जनसंख्या सूचकांक (टीआई)

TI की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाती है:

$$TId = \frac{Td}{Tt} \times 100$$

जहां टीआईडी = डीटीएच केंद्र का तृतीयक जनसंख्या सूचकांक

टीडी = डीटीएच केंद्र की तृतीयक जनसंख्या

टीटी = जिले में कुल तृतीयक जनसंख्या

अंत में, इन तीन सूचकांकों का औसत मान लेने के बाद, समग्र कार्यात्मक सूचकांक

सीएफआई) की गणना एक विशेष सेवा केंद्र के लिए की गई है।

8.2.3 सेवा केंद्र का पदानुक्रम

जिले में 88 ग्रामीण बस्तियों को सेवा केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

केन्द्रीयता स्कोर के आधार पर सेवा केन्द्रों को पाँच भागों में वर्गीकृत किया गया है।

माध्य और मानक विचलन के मान का उपयोग करते हुए पदानुक्रमित आदेश। उन केन्द्रों को निम्न मिलता है।

स्कोर को प्रथम-क्रम सेवा केंद्र के रूप में माना जाता है और उच्चतम स्कोर केंद्र को पांचवें-क्रम के रूप में माना जाता है केंद्र।



8.2.4 प्रथम आदेश सेवा केंद्र

0.1 से 0.25 के केंद्रीयता स्कोर के साथ तैंतालीस केंद्र प्रथम सेवा केंद्र के रूप में चिह्नित हैं।

ये केंद्र सीमित विकल्पों और अपेक्षाकृत कम कार्यों के साथ स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं।

उनमें से अधिकांश उप-डाकघर, प्राथमिक सहकारी जैसी बुनियादी स्तर की सेवाओं से सुसज्जित हैं।

सोसायटी, परिवार नियोजन केंद्र और उप-केंद्र, उप-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बीज और उर्वरक

डिपो, आदि।

8.2.5 द्वितीय-क्रम सेवा केंद्र

द्वितीय क्रम में गिने जाने वाले चौबीस केन्द्र हैं जो बरसठी, सुजानगंज, मीरगंज,

पहाड़पुर, सिंगरामऊ, थाना गद्दी, सुएथा कलां, त्रिलोचन महादेव, धर्मपुर, सिरकोनी,

करंजा कलां, करछुली, देवकली, धनिया मऊ, कचगांव, नेवरिहा, जमुनीपुर, समोधपुर,

सूरापुर, मानी कलां, हबीबपुर, फतेहगंज, सराय डीह, कुँवरपुर जो प्रमुख बाजार हैं

जिला। इन केन्द्रों का केन्द्रीयता स्कोर 0.25-0.5 है। यह उप पीएचसी, वरिष्ठ रहा है

माध्यमिक विद्यालय, कृषि सेवाएँ, सहकारी बैंक, कृषि ऋण समिति, शाखा

प्रभाव क्षेत्र हेतु कार्यालय, रोडवेज बस स्टॉप आदि।

8.2.6 तृतीय आदेश सेवा केंद्र

ब्लॉक और तहसील स्तर पर सोलह केंद्र मौंगरा बादशाहपुर, खेतासराय, खुटहन,

बदलापुर, जलालपुर, रामपुर, नौपेड़ा, मुफ्तीगंज, चंदवक, गौरा बादशाहपुर, बक्शा,

जफराबाद, पाली, महाराजगंज, सिकरारा, जमालापुर को तृतीय क्रम सेवा के रूप में चिह्नित किया गया है

। इस क्रम में केंद्र अधिकतर बड़े बाजार और समग्र सहित ब्लॉक मुख्यालय हैं, केंद्रीयता सूचकांक मान



0.5 से 10 तक होता है। परिवहन सुविधाओं के साथ-साथ स्थानिक स्थान भी ऐसे केंद्रों ने निचले क्रम के केंद्रों से अलग पहचान बनाई है। इसमें कुछ प्रशासनिक भी है पुलिस स्टेशन, डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज, बिजली कार्यालय आदि जैसी सेवाएँ

तालिका 01: जौनपुर जिले में चयनित समारोह के लिए भारित स्कोर

Functional Group	#	Selected Services	Number of Services	Weighted Score
Health	1	Hospital Allopathic	58	56.67
	2	Family Welfare Centre	46	71.45
	3	Maternity And Child Welfare Centre	82	40.08
	4	Veterinary Hospital	46	71.45
	5	Community Health Centre	22	149.40
	6	Primary Health Centre	29	113.34
	7	Primary Health Sub Centre	72	44.41
Education	8	Govt. Secondary School	566	5.80
	9	Govt. Senior Secondary School	151	21.76
	10	Govt. Degree College	37	88.83
	11	Govt.-Polytechnic	4	88.83
Agricultural and Finance	12	Nationalized Bank	145	22.66
	13	Co-Operative Bank	52	63.21
	14	Agricultural Credit Society	224	14.67
	15	Mandis	4	1095.66
	17	Cold Storage	22	149.40
Transport and Communication	18	Branch Office	26	126.42
	19	Post Office	391	8.40
	21	BSNL Exchange	69	47.63
	22	Public Bus Service	188	17.48
Administrative	23	Roadways Bus Stop	33	99.60
	24	Railway Station	32	102.71
	25	National Highway	66.49 km	49.43
	26	State Highway	332.23 km	9.89
	27	Major District Road	219.00 km	7.50
	28	Police Station	27	121.74
	29	Block Headquarters	22	156.52
	30	Tahsil Headquarters	6	547.83
	31	District Headquarters	1	3287.00

8.3 चौथा आदेश सेवा केंद्र

तहसील स्तर पर चार केंद्र मड़ियाहूँ, शाहगंज, मछलीशहर और केराकत हैं



समग्र केंद्रीयता सूचकांक मूल्य सीमा के साथ पदानुक्रम में चौथे क्रम पर कब्जा कर लिया गया है

10 से 20.; ये चार केंद्र तहसील मुख्यालय हैं जिनके सीएफआई मान दस से अधिक हैं

12.99 (मरियाहू), 12.25 (शाहगंज), 12.14 (मछलीशहर), और 11.5 (केराकत)। अपेक्षाकृत उच्च

उच्च भारित सूचकांक और तृतीयक सूचकांक मूल्यों वाले एफसीआई उनकी वर्तमान स्थिति के लिए

जिम्मेदार हैं चौथे क्रम के केंद्र के रूप में। यहां प्रशासनिक संस्थाओं के साथ-साथ ढांचागत सुविधाएं भी हैं

लाभ, अन्य निम्न की तुलना में इसके सापेक्ष कार्यात्मक प्रभाव के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते

हैं-आदेश केंद्र।

8.4 पांचवां आदेश सेवा केंद्र

सीएफआई मान 24.10 के साथ जौनपुर केवल पांचवें क्रम का सेवा केंद्र है। यह जिला है

मुख्यालय और केंद्रीय स्थान पर स्थित है। जौनपुर शहर का जनसंख्या आधार बहुत बड़ा है (180362)।

जर्नल ऑफ ग्लोबल रिसोर्सज, जनवरी 2022, खंड 08 (01) दिनेश कुमार पेज | 70

जिले के व्यक्ति) इस सेवा केंद्र पर अधिकांश कार्यात्मक सेवाएँ उपलब्ध हैं।

भारी मात्रा में और सर्वोत्तम गुणवत्ता में। यह केंद्र राष्ट्रीय राजमार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है

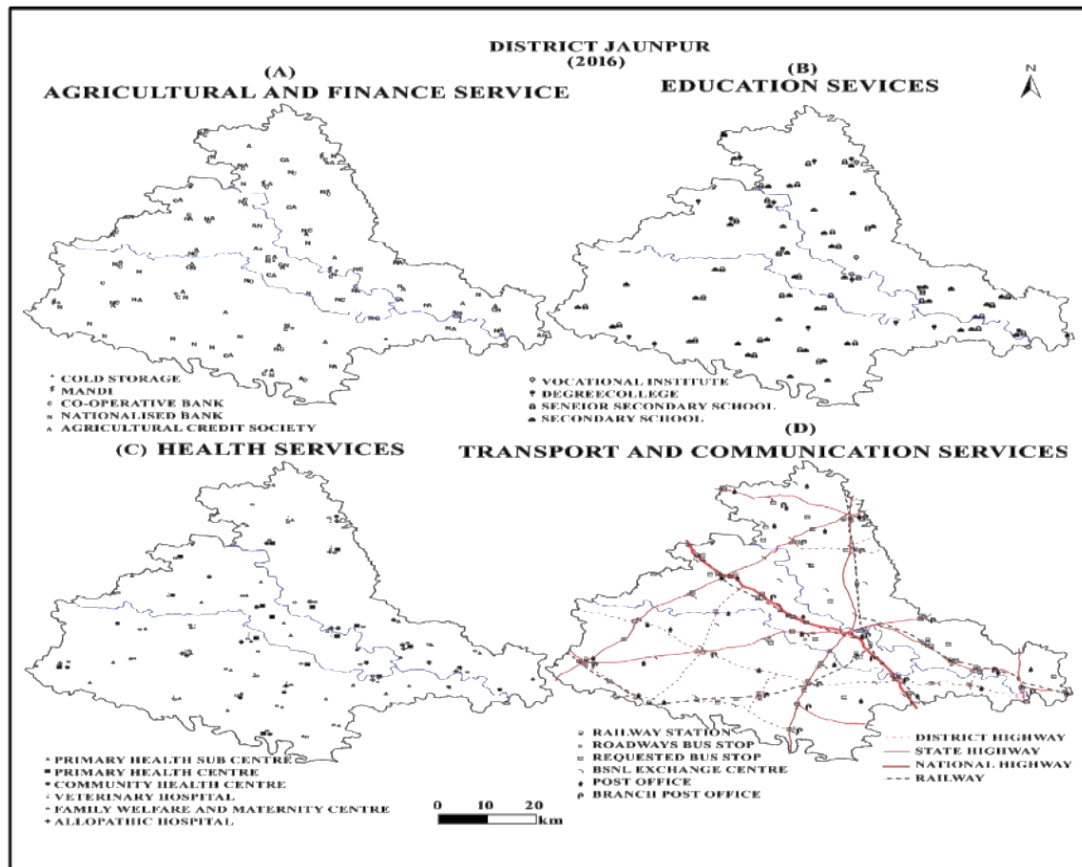
(एनएच-31), दो बड़े रेलवे स्टेशन (जौनपुर जंक्शन एवं जौनपुर शहर) के दोनों मुख्य मार्ग पर हैं

फैजाबाद और सुल्तानपुर के रास्ते लखनऊ, कानपुर और दिल्ली। इसमें जिला मुख्यालय और कई हैं

अन्य सेवाएं। इन्हीं तथ्यों के कारण यह जिले की संपूर्ण धमनी के लिए हृदय का कार्य करता है।

विशाल भीतरी इलाकों में वस्तुओं और सेवाओं को पंप करना।

चित्र 02: कार्यात्मक केन्द्रीयता सूचकांक मान



8.5 सेवा केन्द्र का पूरक क्षेत्र

सेवा केन्द्रों के पूरक क्षेत्र का अनुमान सेवा केन्द्रों की पहचान के बाद,

कार्यात्मक पदानुक्रम में प्रत्येक स्तर पर प्रभाव क्षेत्र का आकलन बहुत चुनौतीपूर्ण है।

सेवा केंद्र अध्ययन का कार्य. वह क्षेत्र जिसे किसी विशेष केंद्र द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, उसे उसका क्षेत्र कहा जाता है।

पूरक क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र या भीतरी प्रदेश। वर्तमान अध्ययन में, का प्रदूषण

पूरक क्षेत्र निम्नलिखित विधियों द्वारा किया गया है:

1. एक सांख्यिकीय या सैद्धांतिक विधि



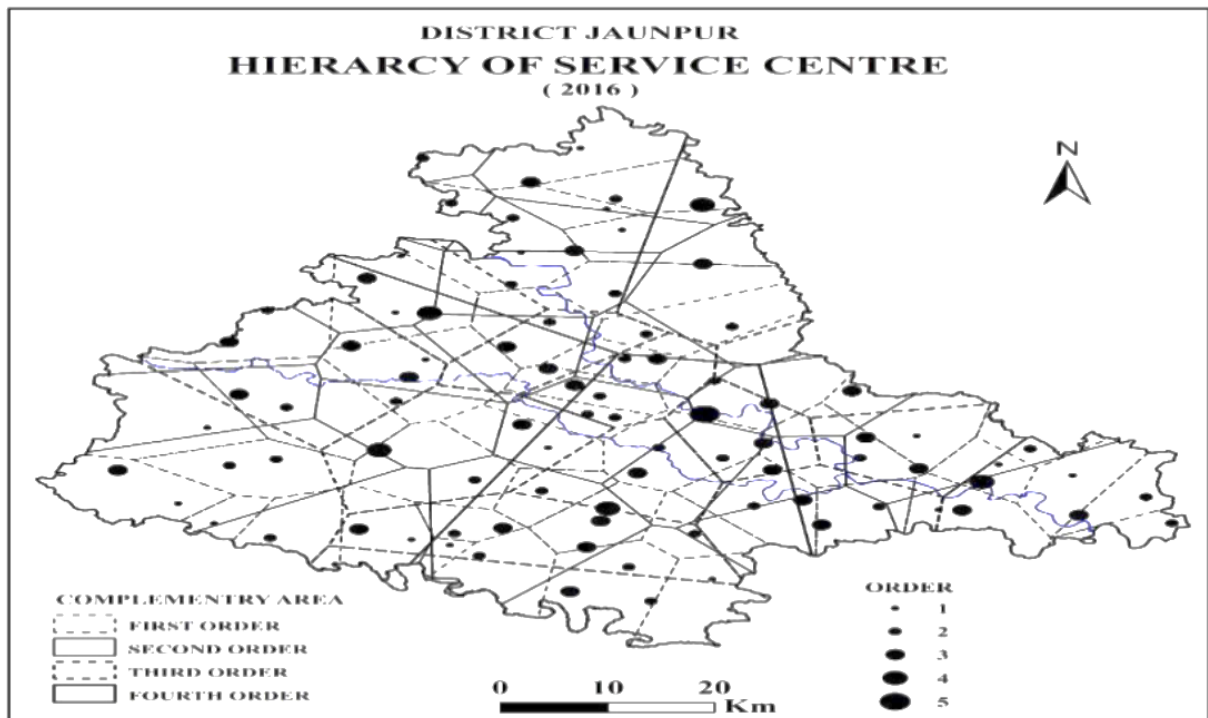
2. गुणात्मक या अनुभवजन्य विधियाँ

फिर 'ब्रेकिंग पॉइंट इक्वेशन' की बेरी विधि द्वारा बाजार के भीतरी इलाकों को प्राप्त किया जाता है

थिएसेन पॉलीगॉन विधि (1911) के साथ खुदरा वितरण केंद्र। इस विधि का प्रयोग किया गया है

वर्तमान जांच में दो केंद्रों के बीच सेवा क्षेत्र की सीमा का सीमांकन करना।

चित्र 03: सेवा केंद्र का पदानुक्रम



43 प्रथम श्रेणी सेवा केंद्र हैं जो आसपास के लोगों को छोटे पैमाने पर सेवाएं प्रदान करते हैं

गाँवा इन क्रमों का भीतरी भाग लगभग 45 वर्ग कि.मी. है। दो केन्द्रों के बीच की दूरी

लगभग 5 से 7 कि.मी. है। हालाँकि, प्रथम क्रम केंद्रों से संबंधित कुछ स्थानिक अंतराल चिह्नित किए गए थे



विश्लेषण के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की उचित आपूर्ति के लिए उचित विचार की आवश्यकता होती है जमीनी स्तर। दूसरे क्रम के 25 केंद्र मुख्यतः तीसरे क्रम की सेवा के बीच स्थित हैं

केंद्र और उस बस्ती की सेवा करें जो लगभग 10 किमी दूर स्थित है। इन आदेशों के भीतरी क्षेत्र हैं

लगभग 90 वर्ग कि.मी. सोलह तिहाई क्रम के केंद्र ज्यादातर ब्लॉक मुख्यालयों और बाजार केंद्रों के हैं।

इन केन्द्रों और इनके पूरक क्षेत्र के बीच की औसत दूरी लगभग 15 कि.मी. है

ऑर्डर लगभग 190 किमी² है। चार ऑर्डर सेंटर पक्की सड़क से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। ये हैं

अधिकतर जिला मुख्यालय के आसपास लगभग 25 से 30 किमी की दूरी पर स्थित है

इन आदेशों का पूरक क्षेत्र लगभग 800 वर्ग किमी है। अध्ययन का सम्पूर्ण क्षेत्र है

सेवा केंद्र के पांचवें क्रम का पूरक क्षेत्र। अध्ययन क्षेत्र के लोग पूरी तरह से हैं

इन केन्द्रों में प्रशासनिक कार्यों के लिए निर्भर। (चित्र.3).

9. निष्कर्ष

निष्कर्ष बिंदु यह है कि कोई भी स्थायी बस्तियाँ जिनके कुछ कार्य हैं। आसपास के क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवा केंद्र के रूप में जाना जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र मध्य गंगा मैदान के पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है और कवर 4035 है वर्ग किमी। 44,94,204 व्यक्तियों की जनसंख्या के साथ। इस अध्ययन में कुल 88 संभावित गाँव हैं।

भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक प्रगति हासिल करना बहुत जरूरी है



बेहतर मानव कल्याण के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, नीति उद्देश्य प्राप्त करना है कृषि, उद्योग आदि जैसे आर्थिक क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र का विकास सेवाएँ। ऐसे उद्देश्यों के बावजूद, पूरे भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर में असमानता है राज्य एक सतत विशेषता रही है।

नीति निर्माताओं को यह समझने की जरूरत है कि सापेक्ष और पूर्ण हस्तक्षेप कहां है।

जरूरत सबसे ज्यादा है। इस प्रकार, इस पेपर में संकेतकों का उपयोग करके उत्तर प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास की जांच की गई जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से। नतीजों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यूपी घनी आबादी वाला राज्य है ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तर की जनसंख्या सघनता होना। यह वास्तव में राज्य की अर्थव्यवस्था को कठिन बना देता है शहरीकरण और आधुनिकीकरण का लाभ उठाएं। हालाँकि, पिछले एक दशक और पाँच वर्षों में परिदृश्य थोड़ा सुधार हुआ है और यूपी में शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिणामों से यह भी पता चलता है कि कृषि, उद्योग और विनिर्माण का प्रदर्शन अभी भी संतोषजनक नहीं है। और, सेवाओं का प्रदर्शन

हाल के वर्षों में यह क्षेत्र बेहतर रुझान दिखा रहा है।

चूँकि स्वास्थ्य एवं शिक्षा ही इसकी आधारशिला रखते हैं किसी अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक विकास में स्वास्थ्य का प्रदर्शन यूपी के संदर्भ में देखा गया है और शिक्षा संतोषजनक नहीं है। इसके परिणामस्वरूप यूपी में सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों का प्रदर्शन खराब रहा बेरोजगारी, गरीबी और असमानता की निरंतरता जो राज्य की समृद्धि को पीछे खींच रही है। इसलिए,



यूपी की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास दर पर पहुंचाने के लिए उचित योजनाओं और नीतियों के माध्यम से हस्तक्षेप करना आवश्यक है प्रक्षेपवक्र।

(केंद्रों) को मानदंडों पर विचार करके केंद्रों के पदानुक्रम स्तर को मापने के लिए चुना गया है केंद्रीयता कार्य सूचकांक (सीएफआई), कार्यशील जनसंख्या सूचकांक (डब्ल्यूआई) और तृतीयक जनसंख्या सूचकांक (टीआई)।

ऐसे तैंतालीस केंद्र हैं जिन्हें प्रथम सेवा केंद्र के रूप में चिह्नित किया गया है जिनका केंद्रीयता मान 0.1 है से 0.25. इन केंद्रों ने उप-डाकघर, प्राथमिक सह-जैसी प्राथमिक सेवाएं प्रदान की हैं दूसरे में ऑपरेटिव सोसायटी, परिवार नियोजन केंद्र और उपकेंद्र आदि चौबीस केंद्र- 0.25 - 0.5 के केंद्रीयता स्कोर वाला ऑर्डर।

इसे प्रभाव क्षेत्र के लिए उप पीएचसी, शाखा कार्यालय, रोडवेज बस स्टॉप आदि की सेवाएं प्रदान की गई हैं। ब्लॉक पर सोलह तृतीय क्रम केंद्र स्तर एवं तहसील मुख्यालय (केंद्रीयता सूचकांक 0.5 से 10), जैसी प्रशासनिक सेवाएँ हैं

पुलिस स्टेशन, डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज, बिजली कार्यालय आदि जबकि चार केंद्र तहसील में हैं चौथे क्रम के रूप में मरियाहू, शाहगंज, मछलीशहर और केराकत का स्तर। यहां ही इसके पीछे प्रशासनिक संस्थानों के साथ-साथ ढांचागत फायदे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अन्य निचले क्रम के केंद्रों की तुलना में सापेक्ष कार्यात्मक प्रभाव। और सीएफआई मूल्य के साथ जौनपुर 24.10 केवल पांचवें क्रम का सेवा केंद्र है। इसमें जिला मुख्यालय और कई अन्य सेवाएँ हैं, यह जिले की संपूर्ण धमनी के लिए हृदय के रूप में काम करता है, वस्तुओं और सेवाओं को व्यापक रूप से पंप करता है भीतरी इलाकों पहले क्रम के भीतरी इलाके लगभग 45 वर्ग किमी, दूसरे क्रम के लगभग 90 वर्ग किमी, तीसरा ऑर्डर लगभग 190 किमी², चौथा ऑर्डर लगभग 800 किमी² और पांचवां ऑर्डर सर्विस सेंटर कवर जिले का समस्त क्षेत्रफल।



10. संदर्भ

1. बेरी, बी.जे.एल. (1967)। बाज़ार केंद्रों और खुदरा वितरण का भूगोल, प्रेंटिस हॉल: एंगलवुड

क्लिफ्स, लंदन, पी. 41.

2. ब्रेसी, एच.ई. (1953) ग्रामीण सेवा केन्द्रों के रूप में शहर। जनसंख्या का लेन-देन. ब्रिटिश संस्थान

भूगोलवेत्ता, खंड 19, पृ. 95-105।

3. ब्रश, जे.ई. (1953)। दक्षिण-पश्चिमी विस्कॉन्सिन में केंद्रीय स्थानों का पदानुक्रम। भौगोलिक

समीक्षा, खंड 43, पृ. 380-402

4. चतुर्वेदी, आर. (2013)। सेवा केंद्रों का पदानुक्रम: इलाहाबाद जिले, उत्तर का एक केस अध्ययन

प्रदेश, नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल ऑफ इंडिया वॉल्यूम 59(2) आईएसएसएन: 0027-9374/1488,

पीपी. 95-104

5. क्रिस्टेलर, डब्ल्यू. (1933). दक्षिण जर्मनी में केंद्रीय स्थान (बास्किन, सी.डब्ल्यू. द्वारा अनुवादित)।

शागिर्द कक्ष:

एंगल लकड़ी की चट्टानें

6. कायस्थ, एस.एल., और मिश्रा, एस.पी. (1981)। कार्यात्मक पदानुक्रम की पहचान करने के लिए एक

पद्धतिगत दृष्टिकोण

ग्रामीण बस्ती-मध्य गंगा मैदान में केराकत तहसील (जौनपुर) का एक केस स्टडी, एल. आर. सिंह में

(ईडी)। भूगोल में नए परिप्रेक्ष्य. थिंक्स लाइब्रेरी: इलाहाबाद, पृष्ठ 123-133।



7. खान, एस., अहमद, ए.(2013)। "ग्रामीण निपटान का पदानुक्रम: क्षेत्रीय संतुलन के लिए एक रणनीति

अलीगढ़ जिले में विकास, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, खंड 2(9) आईएसएसएन नंबर।

22778179, पृ. 194-197.

8. लॉस्च, ए.(1954).द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन, न्यू हेवन: येल यूनिवर्सिटी प्रेस

9. मल्लिक, आर.के. (1998)। ग्रामीण योजना और प्रबंधन के लिए स्थानिक और गुण डेटाबेस का विकास

केंद्रपाड़ा जिला, उड़ीसा, भारत में सेवा केंद्र: एक जीआईएस आधारित जानकारी। अप्रकाशित थीसिस.

10. मंडल, आर.बी. (1960)। "क्लासिकल सेंट्रल प्लेस थ्योरी- सेंट्रल प्लेस सिस्टम", आर.3 में। मंडल और

वी.एन.पी. सिन्हा (ईडी) भूगोल में हालिया रुझान और अवधारणाएं, III, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली,

11. मिश्रा, आर.पी., सुंदरम, के.वी. और राव, पी. (1974)। क्षेत्रीय विकास के लिए एक नई रणनीति, क्षेत्रीय में

भारत में विकास और योजना, विकाश पब्लिशिंग हाउस, प्रा. लिमिटेड दिल्ली, पृ. 204-205.

12. मिश्रा, एस.पी. (1985)। ग्रामीण विकास के लिए सेवा केंद्र रणनीति: एक केस स्टडी। ग्रामीण व्यवस्था, खंड

3 (3), पृ. 227-237.



13. मिश्रा एस.पी. (1981/1985)। एकीकृत ग्रामीण क्षेत्र विकास एवं योजना: एक भौगोलिक अध्ययन

केराकत तहसील जिला जौनपुर, रतन प्रकाशन, वाराणसी उ.प्र.

14. मिश्रा, आर.पी., और शिवलिंगैह, एम. (1970)। भारत में ग्रामीण विकास के लिए विकास ध्रुव

रणनीति। जर्नेल का

आर्थिक भूगोल संस्थान। भारत, पृ. 33-39.

15. पेरौक्स, एफ. (1950)। आर्थिक स्थान: सिद्धांत और अनुप्रयोग। अर्थशास्त्र का त्रैमासिक जर्नेल,

64, पृ.89-104.

16. सरकार, एस. (2018)। स्थानिक डेटाबेस दृष्टिकोण का उपयोग करके ग्रामीण सेवा केंद्रों का

विश्लेषण- एक केस अध्ययनचंदौली जिले, उत्तर प्रदेश, इंटरनेशनल जर्नेल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल
रिव्यूज, खंड 5(3)आईएसएसएन नंबर 23495138, पीपी 694-704

17. सेन, एल.के. एट अल। (1971). एकीकृत क्षेत्र विकास के लिए ग्रामीण विकास केंद्रों की योजना

बनाना-एक केस स्टडी मायरलगुडा तालुका में। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान, हैदराबाद।

18. सिंह, ओ.पी. (1971)। सेवा केंद्रों के पदानुक्रम को निर्धारित करने की दिशा में: केंद्रीय के लिए एक

पद्धति स्थान अध्ययन. नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नेल ऑफ इंडिया, 17(4), पृ. 171-172.

19. सिंह, एस.बी. (1977). सुल्तानपुर जिले में ग्रामीण केंद्रीय स्थानों का वितरण, केंद्रीयता और

पदानुक्रम (यू.पी.), भारत। नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नेल ऑफ इंडिया, 23(3&4), पृ. 185-194

20. स्माइल्स, ए.ई. (1944)। इंग्लैंड और वेल्स में शहरी पदानुक्रम। भूगोल, 29, पृ. 41-51.

थोराट, यू., (2006ए)।



21. वित्तीय समावेशन और सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, 239-243।
22. संयुक्त राष्ट्र। (2006)। विकास के लिए समावेशी वित्तीय क्षेत्रों का निर्माण, ब्लू बुक। आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग.न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।
23. विश्व बैंक। (2008)। सभी के लिए वित्त?: पहुंच के विस्तार में नीतियां और नुकसान (विश्व बैंक नीति अनुसंधान पत्र), विश्व बैंक, वाशिंगटन डी.सी.
24. विश्व बैंक। (2009)। गरीबों को बैंकिंग: 54 अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग पहुंच को मापना। विश्व बैंक, वाशिंगटन डी.सी.